ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-7* August- 2020
Innovation The Research Concept

भारत के मुकाबले चीन का नेपाल में बढ़ता प्रभाव : एक अध्ययन

China's growing influence in Nepal compared to India: A study

Paper Submission: 16/08/2020, Date of Acceptance: 28/08/2020, Date of Publication: 27/08/2020

सत्येन्द्र कुमार
शोध–छात्र,
विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग,
बी.आ.ए.बिहार विश्वविद्यालय,
मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत

सारांश

नेपाल हिमालय पर बसा एक छोटा सा प्रदेश है। यह चीन से लगभग 1236 किलोमीटर एवं भारत से लगभग 1860 किलोमीटर लम्बी सीमा रेखा साझा करता है। नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था की बात की जाय तो 1768 ई. में पृथ्वी नारायण साह ने राजतंत्रीय सत्ता की स्थापना की और यह राजसत्ता 240 वर्षों की कार्यकाल को पूरा करते हुए राजा ज्ञानेन्द्र के कार्यकाल में 2008 में लोकतांत्रिक आंदोलनों के सामने दम, तोड़ता नजर आया और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। नेपाल दो बड़े प्रदेश चीन और भारत के बीच बसा एक छोटा प्रदेश है। जिस पर दोनों देशों के विदेश नीति का गहरा प्रभाव पड़ता है। एक समय ऐसा भी था जब नेपाल पर भारतीय विदेश नीति पूरी तरह से हावी थी। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा माना जाता है कि किसी भी देश की विदेश नीति स्थायी नहीं हो सकती वह राष्ट्रहित के आधार पर ही तय होती है। नेपाल अपने राष्ट्रहित को देखते हुए कभी भारत से रिश्ते मजबूत करने का प्रयास करता है तो कभी चीन से। भारत और नेपाल के बीच वर्त्तमान रिश्ते का निर्धारण भारत–नेपाल मैत्री संधि 1950 से माना जाता है तो चीन के साथ चीन द्वारा तिब्बत के अधिग्रहण के आसपास के समय से और विशेष रूप से 1954 ई. से। चीन नेपाल में भारत के प्रभाव को कम करने के लिए अपने विचारधारा के साथ–साथ आर्थिक विकास के मॉडल का सहारा लेते हुए भारत के सामने चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रहा है। चीन हाल फिलहाल के वर्षो में नेपाल के साथ अपने रिश्तों को मजबूती से धार देते हुए भारत से कई गुणा ज्यादा आर्थिक सहयोग का आश्वासन एवं विभिन्न परियोजनाओं में अपनी हिस्सेदारी को बढा रहा है। यह हिस्सेदारी कही न कही नेपाली शासन व्यवस्था का चीन के प्रति बढ़ते झुकाव को दर्शा रहा है जो भारतीय विदेश नीति को तगरा झटका लगता हुआ प्रतीत हो रहा है।

Nepal is a small region on the Himalayas. It shares a long border line of about 1236 km from China and about 1860 km from India. Talking about Nepal's political system, Prithvi Narayan Sah established monarchical power in 1768 AD, and this state, having completed 240 years of tenure, was seen breaking in front of democratic movements in 2008 under King Gyanendra and A democratic system was established. Nepal is a small region between China and India. Which has a profound impact on the foreign policy of both countries. There was a time when Indian foreign policy was completely dominated by Nepal. But in international politics it is believed that the foreign policy of any country cannot be permanent, it is decided on the basis of national interest. In view of its national interest, Nepal sometimes tries to strengthen relations with India and sometimes with China. The current relationship between India and Nepal is believed to have been determined by the Indo-Nepal Friendship Treaty since 1950, then by the time surrounding the acquisition of Tibet by China with China, and especially since 1954 AD. China is presenting challenges to India by resorting to its ideology as well as economic development model to reduce India's influence in Nepal. China has been strengthening its relations with Nepal in recent years, assuring India many times more economic cooperation and increasing its stake in various projects. This stake is reflecting the growing inclination of the Nepalese regime towards China, which seems to be a major setback to Indian foreign policy.

मुख्य शब्द : विदेशनीति, विचारधारा, प्रभाव, आर्थिक विकास, परस्पर, सहयोग।

Foreign Policy, Ideology, Influence, Economic Development, Mutual Cooperation.

प्रस्तावना

चीन और नेपाल का सम्बन्ध सर्वप्रथम सातवीं शताब्दी में स्थापित हुआ जिस समय तिब्बत के महान शासक सांगत्सेन गैम्पों थे।[1] वहीं भारत नेपाल सम्बन्ध शताब्दी पुराना होते हुए लिखित रूप से सुगौली की संधि 1816 ई. एवं 1923 ई. से ब्रिटिश भारत से मानी जाती है। वर्तमान सम्बन्धों की बात करें तो इसकी शुरूआत भारत–नेपाल मैत्री संधि 1950 से एवं चीन के साथ 1955 से कूटनीतिक संबंधों के शुरूआत से होती है। चीनी प्रधानमंत्री चाऊ एन.लाई ने 23 सितम्बर 1954 को चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि चीन नेपाल के साथ समानता के आधार पर कूटनीतिक सम्बंध बनाना चाहेगा। वांडूग काफ्रेंस में चीनी और नेपाली प्रतिनिधियों के बीच वार्ता के फलस्वरूप अगस्त, 1955 में कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए।[2] कूटनीतिक सम्बंध स्थापित होने के पश्चात चीन नेपाल से सक्रियता बढ़ाने लगा और नेपाल को आर्थिक मदद देना प्रारंभ किया। हालांकि प्रारंभिक वर्षो में नेपाल चीन सम्बंधों को भारत ने समर्थन अवश्य किया था लेकिन राजा महेन्द्र की अधिक सक्रियता ने भारत को अपनी सामरिक एवं आर्थिक सुरक्षा संकट में नजर आने लगी। नेपाल, भारत और चीन के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास शुरू कर दिया। नेपाल से भारत तीन तरफ से सीमा साझा करता है जिससे भारत के संस्कृति और आर्थिक विकास के मामलों में नेपाल भारत पर अत्यधिक निर्भर है। इसी निर्भरता को कम करने के लिए नेपाल चीन से अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है।

महाराजा महेन्द्र ने चीन समर्थक टंक प्रसाद आचार्य को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जिन्होंने भारत नेपाल के मध्य न केवल व्यापार वाणिज्य संधि के संशोधन और परिवर्तन का अनुरोध किया बल्कि तराई क्षेत्र में भारतीय मुद्रा के प्रचलन पर रोक लगा दी।[3] 25 सितम्बर, 1961 को नेपाल नरेश महेन्द्र महारानी रत्ना और विदेश मंत्री चीन के लिए रवाना हुए। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य चीन–नेपाल सीमा संधि पर विचार–विमर्श और हस्ताक्षर करना था। वे भारत को प्रभावित कर के चीन के अनुसार सीमा समझौता करने एवं इसके आर्थिक पक्ष को देखे तो पता चलता है कि 'काठमांडू–कोदारी' मार्ग जैसे सामरिक महत्व का समझौता किया गया। इस तरह चीन के लिए ठण्डे मौसम में भी काठमांडू पहुंचना आसान हो गया। चीन त्रिभूवन राजमार्ग होते हुए बिहार राज्य के रक्सौल तक पहुँच सकता है। भारत का पूर्वाचल और उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग उसके पहुँच में है। चीन पाकिस्तानी मित्रता और सुविधाओं का प्रयोग करते हुए अब भारतीय सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि सीधे दक्षिण एशिया के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न कर सकता है।[4]

भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश सब सड़क मार्ग से उसकी पहुँच में है। लेखक एल.ई.रास का कथन है कि इस पथ ने चीन के लिए हिमालयी अवरोध सदा के लिए समाप्त कर दिया है और नेपाल की भू–राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल दी है।[5] चीनी प्रधानमंत्री चाउ एल.लाई काठमांडू की यात्रा के समय यह कहा था ''नेपाल व चीन का रिश्ता खून का रिश्ता है। इस रिश्ते में कोई जहर नहीं घोल सकता।'' परंतु उस समय चीन और भारत के सम्बंध खराब होने की वजह से नेपाल चीन को एक संतुलन के रूप में इस्तेमाल कर रहा था।[6] महाराजा महेन्द्र यह मानते थे कि नेपाल के आंतरिक प्रशासन में घटने वाली घटनाओं और जन–आंदोलन के पीछे भारत का हाथ है। महाराजा महेन्द्र तेजी से चीन के साथ मित्रता बढ़ाने लगे। नेपाल को चीन से समुचित आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। चीन–नेपाल आर्थिक सहयोग में वृद्धि हुई और भारत के साथ शक्ति संतुलन के प्रयास में भारत पर निर्भरता कम हुई। चीन इन परिवर्तनों से लाभ उठा रहा था। उसने भारत विरोधी भावना को बढ़ा दिया और काठमांडू कोदारी सड़क के निर्माण का अधिकार प्राप्त किया।[7]

नेपाल और चीन के बीच सम्बन्धों में उस समय और मजबूती आई जब भारत से बिना पूछे एवं भारत नेपाल मैत्री संधि 1950 का उल्लंघन करते हुए 1988 में नेपाल ने चीन से हथियार का सौदा किया उस समय भारत के तात्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नेपाल को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर पाबंदी लगा दी। क्योंकि नेपाल नरेश ने चीन के हथियार खरीद उस समय की जब नेपाल में आपातकाल लागू था। ऐसी स्थिति में भारत सहित अमेरिका और ब्रिटेन ने भी हथियारों के सप्लाई पर पाबंदी लगा दी थी तब अमेरिका ने चीन से आग्रह किया था कि वह नेपाल में लगी राजनीतिक आग को भड़काना बंद करें।[8] चीन दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव जमाने और दबाव बनाने के उद्देश्य से पाक के साथ मिलकर नेपाल की मदद से भारत को भय दिखाकर उसके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा करने में लीन है। नेपाल के प्रति चीन के इरादों की झलक माओं के इस कथन से स्पष्ट होता है ''नेपाल और भूटान चीनी भू–भाग के ही अंग है।'' यही नहीं चीन नेपाल को अपने तिब्बती रूपी पंजें की पाँच उंगलियों में से एक मानता है। अभी तक जो भी हुआ है, नेपाल में पाकिस्तानी आई.एस.आई. की बढ़ती गतिविधियाँ, माओवादी गतिविधियाँ तथा नेपाल में बढ़ रहे चीनी प्रभाव एवं उसे शांति के क्षेत्र के रूप में मान्यता दिलाने की चीनी कोशिशों से भारत–नेपाल संबंधों में टकराव की आंशका को बल दिया है।[9]

1990 के दशक में नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थक आंदोलनकारियों द्वारा जन आंदोलन चलाया गया। भारत इस आंदोलन के पक्ष में था। इस काल में भारत–नेपाल सम्बंध मधुर रहे लेकिन 1994 में नेपाल में साम्यवादी सरकार अर्थात मनमोहन अधिकारी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात् भारत–नेपाल सम्बंधों में तनाव दिखाई देने लगा, जब 1995 में मनमोहन अधिकारी ने भारत यात्रा के समय सम्बंधों की पुर्नसमीक्षा की बात कही। इसके पश्चात् मनमोहन अधिकारी भारत नेपाल संबंध सौहार्दपूर्ण बनी रहे इसके लिए उन्होंने कई कदम

उठाए। 2001 में परिवार सहित महाराज विरेन्द्र की हत्या के पश्चात नेपाल की राजनीति व्यवस्था जन आंदोलनों के आगोस में चला गया और नेपाल में सदा के लिए राजतंत्र समाप्त हो गया। इस जन आंदोलन का समर्थन भारत कर रहा था वही चीन राजा के कार्यवाही का। 2005 में चीन और नेपाल के बीच स्थापित कूटनीतिक सम्बन्धों की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई।[10] नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन 2006 ई. में हुआ। जिसमें नेपाली कांग्रेस के साथ माओवाद समर्थक पार्टियाँ भी शामिल थी जो चीनी विचारधारा का समर्थन करता है। नेपाली कांग्रेस भारतीय विचारों के समर्थक रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत–नेपाल सम्बंध काफी उतार चढ़ावपूर्ण बना हुआ है। नेपाल में चीन का हित सिर्फ तिब्बतियों पर नजर रखने के लिए नही है बल्कि इस क्षेत्र में भारत को उलझाना भी है। दक्षिण एशिया में चीन के व्यापक रणनीतिक गठबंधन के लिए नेपाल एक लांच पैड बन गया है। एक बेल्ट एक रोड (ओ.बी.ओ.आर) परियोजना में नेपाल की भागीदारी स्पष्ट रूप से बीजिंग के सामरिक हितों को स्पष्ट करती है और चीन ने काठमांडू में नेपाल के प्रमुख सहायता दाता और निवेशक के रूप में भारत से बढ़त हासिल की। भारत–नेपाल सीमा के साथ मधेसी संकट के कारण नाकेबंदी ने नेपाली आबादी के एक बड़े हिस्से को नाराज कर दिया है जिससे चीन का न केवल इंटरनेट सेवाओं बल्कि वैकल्पिक व्यापार मार्गों के जरिए भारत के विकल्प के रूप में कदम उठाने का अवसर प्रदान किया। नेपाल मुख्य आपूर्ति विशेष रूप से इंधन के मामले में भारत पर अपनी निर्भरता को संतुलित करने के लिए अधिक से अधिक चीनी हस्तक्षेप की मांग की। इसी अशांत समय के दौरान जब चीन ने न केवल नेपाल की रणनीति व्यवस्था में विशाल राजनीतिक स्थान बना लिया था, बल्कि नेपाली लोगों के दिल और दिमाग में भी, नाकेबंदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और राजनीतिक सम्बंधों को तनावपूर्ण बना दिया साथ ही सरकार और नेपाल के लोगों के बीच भारत विरोधी भावना को बढ़ा दिया। मधेशियों को संविधान में पर्याप्त जगह प्राप्त न होने के कारण 23 सितम्बर 2015 से सीमा के रास्तों को अवरूद्ध कर दिया। नाकेबंदी की तीव्रता पर भारत से महत्वपूर्ण ईंधन की आपूर्ति बंद कर दिया गया। परिणामस्वरूप नेपाल ने चीन की ओर रूख किया और 28 अक्टूबर, 2015 को पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने के लिए चीन राष्ट्रीय संयुक्त तेल निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। चीन ने जिलोंग में सीमा पार बिन्दु खोला जो तिब्बत और नेपाल को जोड़ता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम उत्पादों और राज्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए किया गया। 10 नवम्बर 2015 से 10 दिसम्बर 2015 तक चीन ने लगभग 6000 टन कार्गो का निर्यात किया जिसका मूल्य नेपाल में 43.5 मिलियन डॉलर था। दिसम्बर 2015 में नेपाल ने चीन को चीन–नेपाल सीमा के नजदीक रासुबगढ़ी के टिमौरे में अंतर्देशीय कंटेनर डीपो बनाने की अपनी योजनाओं के लिए सहमति दी जो भू–आबद्ध देशों के लिए एक तरह का शुष्क बंदरगाह होगा। चीन डीपों का निःशुल्क निर्माण करेगा। डीपो नेपाली शहर कीरांग से केवल 16 मील दूर स्थित होगा जहाँ चीन अपने किन्हाई–तिब्बत रेलवे का विस्तार करने का इरादा रखता है।[11]

भारत और नेपाल के बीच आयात और निर्यात का प्रतिशत क्रमशः 60 और 63 है। बाकी का व्यापार 3 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा का है जो भारत के माध्यम से किया जाता है। चीन नेपाल की व्यापारिक मांग का केवल 14 प्रतिशत पर नियंत्रण रखता है, लेकिन अब भारत से नेपाल पारगमन व्यापार को अपनी तरफ स्थानांतरित करने का लक्ष्य बना रहा है।[12] वर्तमान में चीन भारत के मुकाबले नेपाल को अधिक आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। एक तरफ चीन नेपाल में सड़कों एवं जल विद्युत संयंत्रों के विकास के लिए 8.3 अरब डॉलर सहायता राशि देने का आश्वासन दिया है वही दूसरी ओर भारत मात्र लगभग 317 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ही सहयोग दे पाता है। चीन के द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी परियोजना 'वन बेल्ट वन रोड' एक आर्थिक विकास का मॉडल है जिसमें नेपाल को शामिल करने के लिए तिब्बत के ल्हासा को रेलवे मार्ग से जोड़ने के लिए लगभग 8 बिलियन डॉलर की परियोजना पर कार्य का विचार चल रहा है। ओबीओआर से चीन नेपाल में बेहतर रेल और सड़क नेटवर्क का विकास कर रहा है जिसमें आधारभूत संरचना के अंतर्गत पोखरा में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण एक ताज उदाहरण है। चीन नेपाल में भारत विरोधी समूहों को सक्रिय रूप से समर्थन कर रहा है ताकि उत्तराखण्ड के कुमाऊँ और गढ़वाल एवं हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों को पुनः एकीकरण के द्वारा एक वृहद नेपाल का गठन किया जाय। इन क्षेत्रों को नेपाल ने 1816 में सुगौली संधि द्वारा ब्रिटिश भारत को सौंप दिया था।

वर्ष 2016 में भारत–चीन और भूटान में त्रिजक्शन पर उत्पन्न ताजा विवाद डोकलाम विवाद के नाम से जाना जाता है। यह विवाद भारत–चीन सम्बंधों को तनावपूर्ण बना दिया। यह विवाद 72 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चर्चा का विषय बना रहा। इस विवाद के कारण नेपाल में भी चिंता व्यक्त की गई क्योंकि डोकलाम की तरह भारत नेपाल और चीन के बीच भी दो त्रिकोणीयजंक्शन बिन्दु है– एक पश्चिमी नेपाल में लिपुलेख और दूसरा पूर्वी नेपाल में झांसांग चुली में है। नेपाल डोकलाम विवाद के समय इसलिए भी सशंकित था क्योंकि उसे यह महसूस होने लगा कि यदि हमारे त्रिजंक्शन पर यदि दो महाशक्यिाँ भविष्य में टकराती है तो यह नेपाल के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए वह किसी महाशक्ति का समर्थन न करते हुए सीमा पर शांति बनाए रखने के विचारों का समर्थन करता रहा।[13]

चीन नेपाल के साथ अपने सम्बंधों की मजबूती के लिए सैन्य अभ्यास का सहारा ले रहा है। दिसम्बर 2016 में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने घोषणा कीकि वह नेपाल के साथ पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने की योजना बना रहा है। वैसे तो विद्वानों का मत है कि इस अभ्यास से भारत को घबराने की आवश्यकता इसलिए नही है क्योंकि भारत नेपाल के साथ पहले से

सैन्य अभ्यास करता आ रहा है। इसके अलावे अमेरिका नेपाल सैन्य अभ्यास भी हुए है।[14]

अध्ययन का उद्देश्य

चीन अपने विदेशनीति के अन्तर्गत नेपाल में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है और इसके बढ़ते प्रभाव से भारतीय विदेश नीति को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस आलेख का उद्देश्य चीन द्वारा उत्पन्न की गई परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन एवं सुझाव प्रस्तुत करना है।

निष्कर्ष

उपरोक्त आलेख के आधार पर यही कहा जा सकता है कि नेपाल–चीन का सम्बंध सदियों पुराना है लेकिन चीन इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा था। वही दूसरी तरफ देखा जाय तो भारत–नेपाल सम्बंध सदियों पुराना होते हुए प्रत्येक कालखण्ड में प्रासंगिक रहा है। भारत, चीन एवं नेपाल के मध्य वर्तमान कालखण्ड 1950 के दशक से प्रारंभ होता है। इस काल के प्रारंभिक वर्षों में चीन नेपाल में कोई विशेष रूचि नहीं ले रहा था लेकिन 1951 में चीन द्वारा तिब्बत के अधिग्रहण के पश्चात चीन नेपाल के सम्बन्ध कुटनीतिक स्तर पर पहुंच गया। भारत–नेपाल मैत्रि संधि 1950 को नेपाल दोषपूर्ण संधि मानता है। इस संधि से भारत को विशेष स्थिति प्राप्त है जिससे नेपाल दबाव महसूस कर रहा है। इस दबाव से उबरने के लिए नेपाल चीन से अपन सम्बंध प्रगाढ़ कर रहा है। जिसकी शुरूआत चीनी प्रधानमंत्री चाउ–एल–लाई के कार्यकाल से हुई जो महाराज महेन्द्र के काल में विशेष रूप से भारत को संतुलित करने का प्रयास किया गया। महाराज विरेन्द्र द्वारा भी चीन के प्रति झुकाव रखने के कारण भारत विरोधी माने गए। नेपाल में 1990 के दशक एवं 2005–06 लोकतंत्र समर्थक नेपाली कांग्रेस और साम्यवादी गुट ने राजसत्ता के विरूद्ध व्यापक जनआंदोलन की शुरूआत की। आखिरकार इस जन–आंदोलन के क्रम में माओवादियों को नेपाली जनता के बीच विशेष स्थान प्राप्त हुआ। विचारधारा के आधार पर माओवादी चीनी विचारधारा के समर्थक होने के कारण चीन के प्रति झुकाव रखते है। वर्तमान में माओवादी विभिन्न पार्टियों के साथ गठबंधन कर सत्ता में हैं। वर्ष 2014 के बाद नेपाल–चीन के संबंधों की बात की जाय तो इसमें काफी विकास देखा गया है चाहे वह नेपाल में भूकम्प आने के समय हो या फिर संविधान के प्रश्न पर मधेशियों के समर्थन में भारत द्वारा नेपाल को की गई नाकेबंदी के समय चीन का नेपाल को सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ और भारत के सम्बंधों में खटास आ गयी।

आवश्यकता इस बात की है कि नेपाल भारत के लिए आर्थिक, सामरिक एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण देश है और चीन, भारत और नेपाल के मध्य तनावपूर्ण सम्बंधों का फायदा उठाकर अपना हित साधने में लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में भारत को अपने राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए अरियल रवैया को दरकिनार करते हुए नेपाल के साथ मधुर सम्बंध कायम करते हुए एवं नेपाल को अधिक से अधिक आर्थिक विकास में सहयोग दे। साथ ही माओवादियों के साथ भी विचारधारात्मक विरोध होते हुए भी शासन सत्ता के साथ सदा सम्पर्क बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि माओवादियों को नेपाल की जनता का समर्थन प्राप्त है। भारत सोंच समझकर कदम उठाए जिससे नेपाली जनता में भारत के प्रति सदियों से जो विश्वास बना हुआ है वह कायम रहे और भारत नेपाल सम्बन्ध प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *एच.गेज, रीजनलिज्म एण्ड नेशनल यूनिटी इन नेपाल, 1976, पृ. 02*
2. *आर.के.साह, नेपालीज पॉलिटिक्स, प. 194*
3. *गोरखा पक्ष काठमांडू, 20 मई 1956*
4. *ए.एस.आसीन, पृ. 215,*
5. *ए.एस.आसीन, पृ. 215,*
6. *शैलेन्द्र कुमारी चतुर्वेदी, भारत नेपाल सम्बन्ध, पृ. 128–129*
7. *पी.पी.काणे एण्ड डब्ल्यू एम.जेकिन्स, दि हिमालय किंगडम पृ. 17*
8. *भारत–नेपाल के सामरिक सम्बंध, 2010, पृ. 182*
9. *shodhganga.ac.in*
10. *shodhganga.ac.in*
11. *डॉ. सलीम अहमद, मोदी सरकार के युग में भारत–नेपाल सम्बंधः चीन से चुनौतियाँ, वर्ल्ड फोकस, फरवरी, 2018*
12. *डॉ. सलीम अहमद, मोदी सरकार के युग में भारत–नेपाल सम्बंधः चीन से चुनौतियाँ, वर्ल्ड फोकस, फरवरी, 2018*
13. *डॉ. सलीम अहमद, मोदी सरकार के युग में भारत–नेपाल सम्बंधः चीन से चुनौतियाँ, वर्ल्ड फोकस, फरवरी, 2018*
14. *डॉ. सलीम अहमद, मोदी सरकार के युग में भारत–नेपाल सम्बंधः चीन से चुनौतियाँ, वर्ल्ड फोकस, फरवरी, 2018*